number employed in the Central Secretariat have not been maintained.

(b) Candidates from Scheduled Castes or Scheduled Tribes have mostly been appointed against reserved vacancies. Statistics are not available to show how many have obtained appointments on merit.

Phosphate Salts in Laccadive Islands

53. Shri A. K. Gopalan: Will the Minister of **Mines and Fuel** be pleased to state:

(a) whether Government are aware that there are possibilities of obtaining phosphate salts from Laccadive Islands; and

(b) if so, what action Government intend to take to prospect the same?

The Deputy Minister in the Ministry of Mines and Fuel (Shri Hajarnavis): (a) Some reports to this effect have been received.

(b) An on-the-spot examination by experts is under way.

Mineral Survey in Bihar

54. Shri Marandi: Will the Minister of **Mines and Fuel** be pleased to state

(a) whether it is a fact that no mineral survey has been carried out in Santhal Parganas of Bihar;

(b) if so, the reasons therefor; and

(c) whether and if so, when Government propose to start such investigation?

The Deputy Minister in the Ministry of Mines and Fuel (Shri Hajarnavis): (a) The Santhal Parganas area has been surveyed for minerals from time to time and as a result of the investigations conducted by the Geological Survey of India, occurrences of coal, clay, agate, iron, kankar, ochre, fire-clay, felspar and quartz have been recorded. The detailed information regarding these occurrences is available in the publications of the Geological Survey of India.

(b) and (c). Do not arise.

कोयले का वितरण

५५. **श्री रामेश्वरानन्द :** क्या खान और ईंधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्र द्वारा जो कोयला आदि राज्य सरकारों को भेजा जाता है उसका व्यापारियों को सही वितरण नहीं होता ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार सीधे ही व्यापारियों को कोयला वितरण करने की कोई योजना बना रही है ?

खान और ईंधन मंत्री (श्री के० दे० मालवीय) : (क) तथा (ख). राज्य सरकारों द्वारा प्रायोजित उपभोक्ताओं के लिए कोयले का कोटा (quotas) विपुल मात्रा में राज्य सरकार को निपटान के लिए दिया जाता है । अपने राज्य में उस कोटा को विभिन्न उपभोक्ताओं में वितरण करने की जिम्मेवारी सम्बन्धित राज्य सरकार की है । केन्द्रीय सरकार के पास सीधे ही व्यापारियों को कोयला-वितरण को अपने हाथ में लेने की कोई योजना नहीं है । ऐसी शिकायत प्राप्त नहीं हुई है कि राज्य सरकारें सही रूप में वितरण नहीं कर रही हैं ।

कर्मचारियों द्वारा उनके अन्य पदों पर नियुक्त हो जाने पर त्याग पत्र देना

५६. **श्री म० लाल त्रिवेदी :**
श्रीमती सावित्री निगम :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि द्वितीय और तृतीय श्रेणी (अराजपत्रित) के केन्द्रीय